

CHARAN SINGH COLLEGE OF EDUCATION & TECHNOLOGY



SADARPUR MEERUT

SESSION - 2023 - 2024

B.Ed - I<sup>st</sup> year

24104587

NAME - Kirtika Chaudhary

CLASS - B.Ed - I<sup>st</sup> year

FILE NAME - mid day meal

Roll No. - 240562000030

SUBMITTED TO

Manoj Kumar

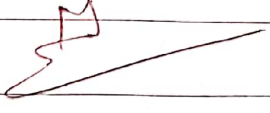
SUBMITTED BY -

Kirtika Chaudhary

CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY MEERUT

TOPIC \_\_\_\_\_

DATE \_\_\_\_\_

| S.No. | Topic                                 | Sign.                                                                              |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | मध्याह्न भोजन योजना                   |  |
| 2     | मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य       |                                                                                    |
| 3     | मध्याह्न भोजन योजना की वित्त व्यवस्था |                                                                                    |
| 4     | मध्याह्न भोजन योजना का क्षेत्र        |                                                                                    |
| 5     | मध्याह्न भोजन योजना की कार्यप्रणाली   |                                                                                    |
| 6     | मध्याह्न भोजन योजना का मूल्यांकन      |                                                                                    |
| 7     | मध्याह्न भोजन योजना की उपलाब्धियाँ    |                                                                                    |
| 8     | मध्याह्न भोजन योजना की कमियाँ         |                                                                                    |

# अभिस्वीकृति

मैं अपने अध्यापक को धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस विषय पर परियोजना बनाने का अवसर प्रदान किया।

मैं अपने सहपाठियों, बुक्कनौ एवं माता पिता को भी धन्यवाद करूँगी जिन्होंने मुझे सीमित समय सीमा के भीतर इस परियोजना को अंतिम रूप देने में मेरी बहुत मदद की है।

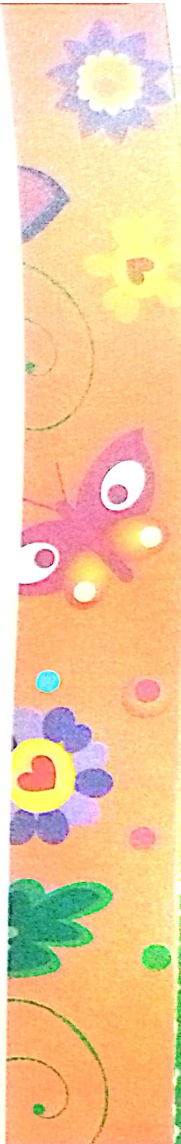
## Mid day Meal

15 August 1947 को हमारा देश स्वतन्त्र हुआ और जनवरी 1950 से हमारे देश में हमारा अपना संविधान लागू हुआ। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में इसकी 45 वीं धारा में स्पष्ट निर्देश था। राज्य इस संविधान के लागू होने तक से दस वर्ष के अन्दर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 1951 से हमारे देश में सभी विकास कार्य योजनावार तरीके से शुरू किए गए। 1957 में केन्द्र में आयोजित भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद् का गठन किया गया और इस प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के संबंध में सुझाव देने का कार्य सौंपा गया। इस परिषद् ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये। परिणामस्वरूप उसके प्रसार में तेजी आई। 1966 में कौटारी आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। इस आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष बल दिया और सरकार का ध्यान पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और कबीलों के बच्चों की शिक्षा की ओर आकर्षित किया गया। साथ ही प्राथमिक स्तर पर होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिये सुझाव प्रस्तुत किया। इसके आधार पर

TOPIC \_\_\_\_\_

DATE \_\_\_\_\_

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1968 की घोषणा की गई।  
 1979 में 6 से 14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिए जो  
 किसी कारण औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे थे  
 निरौपचारिक शिक्षा शुरू की गई। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति  
 की घोषणा की गई। इस शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के  
 सार्वभौमिकरण को राष्ट्रीय ध्येय के रूप में स्वीकारा गया।  
 1987-1988 में ब्लॉक बोर्ड योजना शुरू की गई। थाइलैंड  
 में सबके लिए शिक्षा पर विशेष बैठक हुई जिसमें सबके  
 लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा की गई परिणामस्वरूप  
 संसार के भौतिक दृष्टि से पिछड़े लोगों / वर्गों के देशों में  
 आधारभूत शिक्षा के प्रचार के लिये प्रयत्नों में तेजी आई,  
 हमारे देश भारत में भी 1954 ई. में शैक्षिक दृष्टि से  
 पिछड़े जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू  
 किया गया। 15 August 1995 को पौष्टिक आहार सहायता  
 का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। इसे सामान्यता  
 मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं। इन सब प्रयासों  
 के बाद भी हम प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं  
 कर सके और इस मार्ग पर सबसे बड़ी समस्या थी  
 स्कूल होने पर भी बच्चों का स्कूल में प्रवेश न  
 लेना और प्रवेश लेने के बाद बच्चों का पढ़ाई बीच  
 में छोड़कर चले जाना। प्रवेश लेने के बाद स्कूल



TOPIC \_\_\_\_\_

DATE \_\_\_\_\_

आपत्तय कहते हैं। ये ती इस वीच में प्राथमिक स्कुलो में नोंगाकन बलने के लिये और स्थाप ही आपत्तय को रोकने के लिये अनेक प्रयत्न किरत जस फलतु इस क्षेत्र में सफलता बहुत कम मिली थी। इस के लिये उच्च न्यायालय से केन्द्र और राज्य सरकारों को चैतावनी भी दी गई थी। अतः इन समस्याओं का समाधान करने के लिये केन्द्र सरकार ने 15 अगस्त 1995 में प्राथमिक शिक्षा के पॉलिटिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया तथा इसे संक्षेप में मध्यान्ह भोजन योजना कहते हैं।

### मध्यान्ह भोजन योजना का उद्देश्य

इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

1. बच्चों के प्राथमिक स्कुलो में नोंगाकन में वृद्धि करना
2. बच्चों को प्राथमिक स्कुलो में रोक रखना और इस स्तर पर हीने वाले आपत्तय को रोकना।
3. बच्चों की स्कुलो में उपस्थिति में वृद्धि करना।
4. बच्चों को पॉलिटिक आहार द्वारा स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना।
5. बच्चों को स्कूल स्थान भोजन व्यवस्था कर उनके आति भेद को कम करना।

TOPIC \_\_\_\_\_

DATE \_\_\_\_\_

महानंद भोजन योजना की वित्त व्यवस्था।

यह योजना केन्द्र द्वारा संचालित योजना है। इस योजना के संचालन में केन्द्र और प्रांतीय सरकारें 75:25 के अनुपात में व्यय करती हैं। इसके लिये केन्द्र सरकार प्रांतीय सरकारों को ग्रीड जंचावल व अन्य पारिटक पदार्थ भुईया करती हैं और साथ में स्कूलों में खाद्य सामग्री रखने के लिये एक स्टोर रूम बनाने, भोजन पकाने के लिये 25 विद्यार्थियों पर एक और भोजन पकाने के लिये 25 विद्यार्थियों पर एक रसोइया एवं सहायक की नियुक्ति पर आने वाला व्यय वहन करती है। यदि छात्रों की संख्या 25 से अधिक होती है तो 26 से 100 विद्यार्थियों के लिये दो रसोइयों और दो सहायकों और फिर 100 बच्ची तक पर एक रसोइया एवं एक सहायक पर आने वाले व्यय का खर्च वहन करती है। केन्द्र सरकार प्रांतीय सरकारों को खाद्य पदार्थों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले व्यय के अपर एक निधारित मानदण्ड के तहत साव्हिडी देती है साथ ही योजना के संचालन और उसकी निगरानी पर होने वाले व्यय में भी एक निश्चित मानदण्ड के आधार पर व्यय साझा करती है।

TOPIC \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_

## महयान्त योजना योजना का क्षेत्र

प्रारम्भ में यह योजना योजना देश के 2408 ब्लॉकों में चलाई गयी थी और इसके अन्तर्गत केवल प्राथमिक सरकारी स्कूलों को लिया गया था सन् 1997-1998 में इसे देश के सभी ब्लॉकों में लागू किया गया सन् 2002 में इसमें शिक्षा गारन्टी योजना और वैकल्पिक व्यव नई तरह की शिक्षा के लिये शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत चलाने वाले शिक्षा गारन्टी स्कूल और अल्पसंख्यकों मुख्यालयों के द्वारा चलाया जा रहे मकतब एवं मदरसी को सम्मिलित कर लिया गया इसके बाद सन् 2007 में इस योजना में उच्च स्कूलों को भी सम्मिलित करना शुरू किया। प्रारम्भ में शैक्षिक इकाई से पिछड़े ब्लॉकों को लिया गया और उसके बाद 1 अप्रैल 2008 से सभी ब्लॉकों को इस योजना को लागू कर दिया गया है। वर्तमान में इस योजना में कुछ सरकारी मन्चता एवं आर्थिक सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। सन् 2014-15 में यह योजना 11.58 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में चल रही है। 10-45 करोड़ बच्चों लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में इसकी संख्या में और इजाफा हुआ है।

प्रधानमंत्री योजना की कार्य प्रणाली

2007 में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया था। तब से आज तक केन्द्र सरकार जी भी और जिस प्रकार की भी सहायता इस योजना को चलाने के लिए करती है। उसे सीधे प्रांतीय सरकारों की सर्व शिक्षा अभियान समितियों को भेजी है और ये समितियाँ पूरे प्रान्त में इस योजना को जिला स्तरीय समिति और ग्राम-पंच समिति अथवा स्तरीय समिति और ग्राम-पंचायतों द्वारा स्वामी प्राथमिक स्तर उच्च शिक्षा प्राथमिक स्कुलों में चलाती हैं ये समितियाँ अपने-2 क्षेत्रों में इस योजना के संचालन की निगरानी भी करती हैं। जहाँ तक स्कुलों में मध्यम एवं प्रारंभिक की व्यवस्था का प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों के स्कुलों में यह योजना सामान्यतः स्कुलों में तैयार किया जाता है और बड़े क्षेत्रों में सामान्यतः योजना सफल करने वाले ठेकेदारों द्वारा सफल किया जाता है सरकारों द्वारा के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1-5 के प्रत्येक बच्चे को प्रति स्कुल दिवस 100 ग्राम अनुदान तथा बाल स्वास्थी खाद्य तेल और भत्ता दिये जा रहे हैं और उच्च प्राथमिक

स्कूल कक्षा 6-8 के प्रत्येक बच्चे को प्रति स्कूल दिवस 150 ग्राम अनाज तथा दाल, सब्जी, खाद्य तेल और मसाले दिये जा रहे हैं।

### मध्यान्ह भोजन योजना का सल्याकन

यदि इस योजना का निष्पक्ष दृष्टि से सल्याकन किया जाय तो इससे उपलब्धियाँ और कमियाँ नजर आसकगी।

### मध्यान्ह भोजन योजना की उपलब्धियाँ -

मध्यान्ह भोजन योजना का प्रारम्भ ही इस उद्देश्य से किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा की भाँति इस योजना के कुछ गुण व कुछ कमियाँ का सर्वआमिकरण हो, परन्तु अन्य योजना है। उनके चलते अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो पाया है। फिर भी इस योजना के कुछ गुण की उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं -

1) शिक्षा - साल 2014-15 तक इस योजना की वृद्धि के 11.58 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में लागू किया जा चुका है। इससे देश के लगभग 10-15 लाख करोड़ बच्चे लाभान्वित हैं।

TOPIC \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_

इस योजना के लाभ होने के बाद प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कुलों में नागांकन में लगी से वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों के बच्चों का नागांकन बढ़ा है।

श्री स्त्री स्कुली बच्चों के पाषण में सुधार हुआ है। बच्चों में रुकसाप बैठकर भीजन खाने से जलिय औद्योग में कमी आ रही है, आई-चार बढ़ रहा है।

अपत्य तथा अवैधन में कमी आ रही है।

प्रधान श्री भीजन योजना की कमियाँ -

इस योजना की स्पष्ट कमियाँ टूटि-गै-चर नहीं हैं या प्रमाण रूप में उपलब्ध नहीं हैं। पाली है फिन् श्री यदाकदा अन्ववरी में या दूरदर्शन आदि पर सूचनाएं प्रसारित होती रहती हैं कि क्षेत्र विशेष में भीड़-उमेल योजना में हलने रूपों का चोटाला हुआ है। खाद्य पदार्थों को बेच दिया गया है या पैसा। सहायता, प्राप्त होने के बाद बच्चों को मध्यम और भीजन नहीं दिया जा रहा है। भीजन पकड़ जाने वाले स्थानों में बन्दगी रहती है, परे हुए भीजन में कीड़े-मकौड़े पाल

जाने हैं।

वस्तुतः इस योजना से काफी लाभ हुआ है। परन्तु यदि यह योजना पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ चलाई जाती तो और भी अधिक लाभ होते। इस योजना की निगरानी हेतु ऊपर से नीचे तक अनेक तन्त्र हैं, परन्तु फिर भी धोखा हो रहे हैं, जानकों से निज्ज स्तर का भोजन दिया जा रहा है। धोखाला या लापरवाही होने की स्थिति में जाँच कमेटी बना दी जाती है और कई बार सही परिणाम भी नहीं आ पाते हैं। यदि हम सब कर्मियों को इस किया जा सके तो मध्यमद भोजन योजना की सफलता में कोई संदेह नहीं हो सकता है।

